मेरठ के हस्तिनापुर विस से विधायक दिनेश खटीक ने 9 जून को गंगानगर थाने में दी थी चेतावनी, 19 जुलाई को दिया त्यागपत्र

थाने से उठा विवाद मंत्री के इस्तीफे तक जा पहुंचा

इस्तीफे पर सियासत

मेरठ, मुख्य संवाददाता। जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक का गंगानगर थाने में एक मुकदमे से शुरू हुआ विवाद इस्तीफे तक पहुंच गया। 9 जून की रात मुकदमा दर्ज न होने पर उन्होंने इस्तीफे की चेतावनी दी थी। 19 जुलाई को उपेक्षा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया।

पूरे मामले की शुरुआत 4 जून को हुई थी। उनके एक करीबी टेंट कारोबारी कोमल की दो पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई थी। कोमल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो 9 जून को राज्यमंत्री ने गंगानगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया। मंत्री ने विरोध में धरना दिया और इस्तीफे की धमकी दे डाली।

मामला तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी तक पहुंचा लेकिन बात नहीं बनी। 10 जून को इस्तीफे की घोषणा के लिए उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया को बुलाया। भनक लगते ही भाजपा जिलाध्यक्ष विमल शर्मा पहुंच गए। कहा जाता है कि उस सयम मान मनौव्वल के बाद इस्तीफे की घोषणा टल गई। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली लेकिन क्रास रिपोर्ट भी हो गई। यहां भी मंत्री की किरकिरी हुई।

दिनेश खटीक। ●

संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा है दिनेश खटीक का परिवार

जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक(45) और उनका परिवार शुरू से संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। मेरठ के फलावदा के मूल निवासी दिनेश खटीक का राजनीतिक सफर आरएसएस से ही प्रारंभ हुआ। 1994 में फलावदा में संघ के खंड कार्यवाह बने। 2006 में उन्हें विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल में भी काम करने का मौका मिला। 2007 में भाजपा के जिला मंत्री बने। 2010 में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बनाये गए। 2013 में वे भाजपा के जिला महामंत्री भी बने। साथ ही अनुसूचित मोर्चा में भी जिम्मेदारी मिली। 2017 में भाजपा ने पहली बार हस्तिनापुर से टिकट दिया और विधायक चुने गए। 26 सितंबर 2021 में उन्हें योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2022 में भाजपा से दूसरी बार टिकट मिला। वह हस्तिनापुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए।

हमारी बात नहीं सुनते अधिकारी: दिनेश

दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि विभाग में मेरे आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होती और न ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है। विभागीय अधिकारी सिर्फ गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्यमंत्री का अधिकार समझते हैं। विभाग में तबादलों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। दलित जाति का मंत्री होने के कारण विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है।

राज्यपाल की जगह पहले गृहमंत्री को भेजा इस्तीफा

खटीक ने कहा कि इस संबंध में जब सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग से बात की तो उन्होंने पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। इन्हीं सब बातों से आहत होकर त्यागपत्र देने की बात उन्होंने वायरल पत्र में कही है। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जगह पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफे का पत्र भेजे जाने को दबाव की राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

इस्तीफ में ये लगाए आरोप

- दलित मंत्री होने के नाते मेरे आदेश पर नहीं होती कोई कार्यवाही
- विभागीय बैठकों और योजनाओं की नहीं दी जाती जानकारी
- विभाग में स्थानांतरण सत्र में किया गया भ्रष्टाचार
- मांगने पर भी विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव ने नहीं दी तबादलों की जानकारी
- विभाग में कोई काम नहीं मिला इसलिए नहीं मिलता मेरे पत्रों का जवाब

नाटकीय ढंग से शुरू हुआ घटनाक्रम : मेरठ की हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश खटीक जलशक्ति राज्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की एक बैठक अलग से दोपहर 12 बजे बुलाई गई। इसमें सभी कैबिनेट, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्रियों को बुलाया गया। दिनेश खटीक इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। सूत्रों का कहना है कि एक दिन पहले वह संगठन मंत्री सुनील बंसल से भी मिले थे। इसके बाद मंगलवार को वह राजभवन गए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दे दिया।

दिल्ली दरबार में यूपी के परेशान मंत्रियों का मामला

नईदिल्ली, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर मंत्रियों की नाराजगी और परेशानी का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राज्य सरकार के दो मंत्रियों दिनेश खटीक और जतिन प्रसाद ने अपनी अपनी बात भी पहुंचाई है। सूत्रों के अनुसार खटीक का गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा इस्तीफा वाला पत्र सोशल मीडिया पर आने के बाद पार्टी नेतृत्व में इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए समझाइश जरूर दी है।

सूत्रों के अनुसार अपने ओएसडी के भ्रष्टाचार के मामले में उलझे जतिन प्रसाद ने भी केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई है। मंत्री दिनेश खटीक भी दिल्ली में सक्रिय रहे। इन मामलों में केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे तौर पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन संकेत दिए हैं कि जल्द ही वहां पर सब कुछ ठीक-ठाक कर लिया जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने खटीक के इस्तीफे की चिट्ठी गृह मंत्री को भेजे जाने के मामले पर कहा कि इस्तीफा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा जाता है। इसलिये इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कहीं कुछ नाराजगी होती है उसे दूर कर लिया जाता है।

भाजपा सरकार में चल रहा है भ्रष्टाचार उद्योग : कांग्रेस

कांग्रेस ने मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की दुहाई देती थी, उनके मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि सरकार में सिर्फ एक उद्योग चल रहा है। वह है भ्रष्टाचार उद्योग। मीडिया संयोजक अंशु अवस्थी ने कहा कि दलितों को लेकर जो झूठे प्रेम का दिखावा भाजपा करती थी, मंत्री ने अपने इस्तीफे में उसकी कलई खोल दी है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि भाजपा सरकार में दलितों का अपमान हो रहा है।

भाजपा बताए अब विद्रोह की किसकी बारी: अखिलेश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार में तबादलों को लेकर मची रार पर बुधवार को करारा वार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर न केवल दिनेश खटीक के दलित होने के कारण उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। वहीं, लगातार स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और जलशक्ति मंत्रालय में हो रहे विवाद पर टिप्पणी की।

अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं हो परंतु दलित होने का अपमान मिलेङ्क , ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। भाजपा को बताना चाहिए कि अब विद्रोह करने की किसकी बारी है।

दलित मंत्री की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण: बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भाजपा सरकार में दलित मंत्री की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने बुधवार को खटीक मामले में ट्वीट कर कहा कि इससे सरकार की जातिवादी मानसिकता का साफ पता चलता है।

आमने-सामने

सपा प्रमुख साजिश की जगह अपनी पार्टी बचाएं : केशव

लखनऊ, विशेष संवाददाता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश सरकार को लेकर किए गए ट्वीट पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को केवल वोट बैंक समझने वाले सपाई, बसपाई, कांग्रेसी भाजपा को ज्ञान नहीं दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए डबल इंजन सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख साजिश करने की जगह अपनी पार्टी को बचाएं।

खटीक से रोज बात होती है, वह नाराज नहीं : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। स्वतंत्र देव ने कहा है उनकी जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक से रोजाना बातचीत होती रहती है, वह नाराज नहीं हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है।

मंत्री जितिन प्रसाद ने किया नाराजगी से इनकार

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को तबादला विवाद का पटाक्षेप करने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह बिल्कुल नाराज नहीं हैं। प्रदेश सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। जो भी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी की।

पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत कर खुद के बारे में चल रही अटकलों खारिज किया। उन्होंने न्यूज एजेंसी के एक ट्वीट को री-ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने कहा है-'पीएम मोदी और सीएम

योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर विभाग में अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी ही। एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां भी गड़बड़ी है, वहां कार्रवाई होगी और बदलाव भी होगा। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है।' इससे पहले माना जा रहा था कि वह दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं।

मंकीपॉक्स के बाद मारबुर्ग वायरस ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विश्व भर में कोरोना के बाद कई देशों में मंकीपॉक्स का खतरा अभी बरकरार है। हाल के दिनों में कई देशों में मंकीपॉक्स के मामलों में वृद्धि भी दर्ज की गई है, लेकिन अब कोरोना और मंकीपॉक्स के साथ ही एक नए और बेहद खतरनाक वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम है,मारबुर्ग। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस के मामले अभी कुछ अफीक्री देशों में ही आए हैं। रक्तस्रावी बुखार संबंधी मारबुर्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है।

कोई दवा या टीका नहीं : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, अब तक सामने आए मामलों के आधार पर मारबुर्ग से होने वाली मृत्यु दर 80 फीसदी से अधिक है। घाना से पहले सितंबर 2021 में गिनी में वायरस का एक मामला सामने आया था। कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका व युगांडा में भी मारबुर्ग के मामले सामने आ चुके हैं। वायरस से लड़ने के लिए फिलहाल कोई दवा या टीका नहीं बना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मारबुर्ग, इबोला जितना खतरनाक है। इससे संक्रमित होने पर इंसान को तेज बुखार, डायरिया, उल्टी और सिरदर्द होने लगता है।

चमगादड़ों, अन्य जानवरों से इंसानों में फैलाव : इस संक्रमण पर लगातार अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि मारबुर्ग वायरस चमगादड़ों समेत अन्य जानवरों से इंसान में फैल सकता है। इसके बाद लार या छींक से बाकी लोगों तक पहुंच सकता है। घाना में कई मामलें सामने आने के बाद वहां लोगों को सलाह दी गई है कि वे चमगादड़ों की गुफाओं से दूर रहें और खाने से पूर्व मांस को ठीक से धुलकर अच्छी तरह पकाएं।

ऐसे हुआ नामकरण

1967 में सबसे पहले इस वायरस का पता जर्मनी के मारबुर्ग शहर में चला। उसी आधार पर इसे मारबुर्ग कहा गया। अफ्रीका से लाए गए कुछ ग्रीन बंदरों से यह वायरस शहर में फैला। कुछ ही समय में यह जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट और बेलग्रेड पहुंच गया। साल 1988 से अब तक इस वायरस से पीड़ित अधिकांश रोगियों की मौत हो गई।

मंकीपॉक्स पर केरल में एसओपी जारी

केरल में मंकीपॉक्स के दो मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी। इसके तहत संक्रमित और लक्षण वाले लोगों के लिए पृथक रहने, नमूने एकत्रित करने और उपचार के लिए जानकारी दी गई है।

अपनी रफ्तार से चकित करने भारत आ रहा चीता

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता जल्द भारत में भी दिखेगा। देश में विलुप्त हो चुके चीतों को वापस लाने के लिए भारत ने नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अगले महीने नामीबिया से आठ चीते भारत लाए जाएंगे, जिनमें चार नर और चार मादा होंगे।

ये चीते मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाए जाएंगे। भारत यात्रा पर आई नामीबिया की उप-राष्ट्रपति नानगली म्बुम्बा और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को इस बाबत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत भारतीय वन्य जीव महकमे के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जबकि भारत वन्य जीव संरक्षण के दूसरे क्षेत्रों में नामीबिया को मदद करेगा।

दक्षिण अफ्रीका से भी लाए जाएंगे चीते: पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि नामीबिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए जाएंगे। अगले पांच साल में अफ्रीकी देशों से कुल 30 चीते लाने की योजना सरकार की है।

1952 में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा हुइ

1. मंत्रालय के अनुसार, आजादी से पूर्व देश में चीतों की खासी तादाद थी, लेकिन शिकार के कारण इनकी आबादी घटती गई।

2. 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरया जिले में चार चीते मारे गए थे। इसके बाद 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई।

'मोदी को दंगों में फंसाना चाहती थीं सीतलवाड़'

दावा

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अदालत में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ 2002 में राज्य में हुए दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को फंसाने की साजिश में शामिल थीं। एसआईटी ने बुधवार को यह भी आरोप लगाया कि सीतलवाड़ ने पीड़ितों के नाम पर धन जमा किए और उक्त राशि का इस्तेमाल भाजपा की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में किया।

सीतलवाड़ को अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले महीने पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर. बी. श्रीकुमार और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट के साथ गिरफ्तार किया था। इन पर 2002 के दंगों के आरोप में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़ने का आरोप है। सीतलवाड़ इस समय जेल में हैं और उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी है। एसआईटी ने जमानत अर्जी का विरोध किया है।

सीतलवाड़ की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मितेश अमीन ने अहमदाबाद में सत्र न्यायाधीश डी. डी. ठक्कर की अदालत में कहा कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को दंगों के मामलों में आरोपियों के तौर पर फंसाने की वृहद षड्यंत्र का हिस्सा थीं।

तैयारी | ई-संजीवनी ओपीडी की तर्ज पर शुरू होगी सुविधा, मरीज घर बैठे डॉक्टरों से निःशुल्क सलाह ले सकेंगे

मानसिक रोगियों के लिए ऑनलाइन ओपीडी जल्द

■ मदन जैड़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके तहत ई-संजीवनी ओपीडी की तर्ज पर मानसिक रोगियों के लिए भी जल्द ऑनलाइन ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। देश में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या और डॉक्टरों की कमी के बीच यह कार्यक्रम दूरदराज के क्षेत्रों में मानसिक रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण साबित होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के बेंगलुरु स्थिति संस्थान निम्हंस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। निम्हंस से देश भर के 17 और मानसिक रोग अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद ई-संजीवनी की तर्ज पर ऑनलाइन ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी।

- राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मसौदा तैयार हुआ
- कार्यक्रम दूरदराज में मानसिक रोगियों के लिए अहम साबित होगा

ई-संजीवनी की शुरुआत कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामान्य बीमारियों के लिए की थी, जिसमें अब तक सवा करोड़ से अधिक मरीजों को ऑनलाइन देखा जा चुका है। इसमें पहले रोगी को ऑनलाइन पंजीकरण करना होता था तथा ओटीपी के पुष्टिकरण के बाद एक टोकन प्रदान किया जाता है। इसके बाद मरीज एक ऑनलाइन वेटिंग रूम में प्रवेश करता है और कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों से संपर्क करता है। डॉक्टर से परामर्श के बाद उसे पर्ची डाउनलोड करनी होती है, जिससे वह दवा खरीदता है। इसी मॉडल को मानसिक रोग स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए लागू किया जा रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का मसौदा तैयार है तथा कुछ आवश्यक सुधारों के बाद इसे लागू किया जाएगा। यह भी कोशिश की जा रही है कि पहले सुरक्षा बलों में इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए और उसके बाद देश भर में।

देश 30s

साधु ने आत्मदाह का किया प्रयास

जयपुर। राजस्थान के डीग क्षेत्र में खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर चल रहे साधुओं के आंदोलन के दौरान एक साधु ने बुधवार को आत्मदाह का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार, साधु को गंभीर अवस्था में जयपुर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि धरनास्थल से दूर खड़े एक साधु विजय दत्त ने अचानक ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर खुद को आग लगा ली। पुलिस वाले उसे बचाने दौड़े और आग बुझाकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

अग्निपथ योजना पर 25 अगस्त को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केन्द्र की 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां स्थानान्तरित की गई याचिकाओं से जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उच्चतम अदालत ने 19 जुलाई को योजना को चुनौती वाली याचिकाओं को स्थानान्तरित कर दिया था।

जेईई मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बुधवार को घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मेन स्थगित कर दी गई है। अब यह 21 जुलाई की बजाय 25 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने हालांकि इस महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित करने का कारण नहीं बताया। एनटीए ने कहा,'जेईई-मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा जिसमें करीब 500 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6.29 लाख छात्र परीक्षा देंगे।

भाजपा दो, कांग्रेस एक सीट जीती

भोपाल। मध्य प्रदेश में पांच नगर निगमों में से तीन पर आए महापौर पद के परिणामों में से दो सीटें भाजपा ने निकाली है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि महापौर चुनाव में रीवा में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद व्यास को 10,282 मतों के अंतर से पराजित किया। इससे पहले यह सीट भाजपा के पास थी। देवास में भाजपा की उम्मीदवार गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को 45,884 मतों के अंतर से हराया। वहीं, रतलाम महापौर पद भी भाजपा ने अपने पास बरकरार रखा है।

पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ईडी हिरासत में

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को एनएसई को-लोकेशन घोटाले से जुडे धनशोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नौ दिन की प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े धनशोधन मामले में संजय पांडे को मुंबई से गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत ने ईडी के आग्रह पर संजय पांडे को रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने पांडे को 14 दिन की हिरासत मांगी थी।

एमएसपी समिति पर भगवंत मान ने केंद्र को घेरा

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर गठित समिति में राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने ट्वीट किया, किसानों से किए गए वादे के विपरीत, एमएसपी समिति में पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं देने के केंद्र के निर्णय की मैं निंदा करता हूं। पंजाब के किसान पहले ही फसल चक्र और कर्ज में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी हमारा कानूनी अधिकार है।

बॉलीवुड माफिया कर रहे परेशान : तनुश्री दत्ता

मुंबई। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बॉलीवुड माफिया और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। तनुश्री ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कहा कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए तनुश्री ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि 'मीटू' दोषी और एनजीओ जिनका मैंने खुलासा किया है, वह इस सब के पीछे हैं, वरना मुझे इस तरह निशाना बनाकर क्यों परेशान किया जाएगा?

नवलखा को जेल में फोन सुविधा नहीं दे सकते

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि वह सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जेल से फोन करने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि वह आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 25 मार्च को ऐसी सुविधाओं पर रोक लगा दी थी। नवी मुंबई की तलोजा जेल सहित विभिन्न जेलों में कैदियों के लिए फोन कॉल करने के वास्ते एक 'कॉइन बॉक्स' सुविधा उपलब्ध है, जहां नवलखा और मामले के अन्य आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
कार्पोरेट पहचान संख्या : L74140DL1991PLC046369
पंजीकृत कार्यालय : 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
कारपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर–126, नोएडा– 201304, उ.प्र., भारत टेलीफोन : +91 11 26436336
वेबसाइट : www.hcltech.com; ई–मेल आईडी: investors@hcl.com

विडियों कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") एवं अन्य दृश्य–श्रव्य ("ओएवीएम") माध्यमों के द्वारा आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर "वीसी"/"ओवीएम" के द्वारा आयोजित की जाएगी ताकि बैठक को आयोजित करने के लिए भेजी जा रही सूचना में निर्धारित कामकाज को पूरा किया जा सके।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 एवं अन्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों") के साथ में पठित, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। एमसीए परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और इसके अधीन दिए गए नियमों के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) के साथ कम्पनी के एजीएम का नोटिस उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) कम्पनी की वेबसाइट www.hcltech.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी, नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

एजीएम में रिमोट ई–मतदान/ई–मतदान के माध्यम से वोट डालने का तरीका

क) सदस्यों के पास ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) के माध्यम से एजीएम में निर्धारित किए गए व्यवसायों पर अपना मतदान देने का अवसर होगा। डिमैटिरिलाइज्ड / भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों को ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) को विधि, एजीएम के नोटिस में प्रदान की जाएगी।

ख) ई–मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एजीएम के दौरान ई–मतदान प्रणाली द्वारा मतदान देने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने दूरस्थ ई–मतदान अवधि के दौरान प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं दिया है और ऐसा करने से वे वर्जित नहीं है।

ग) ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉग–इन प्राथमिकताएं (क्रेडेंशियल्स), सदस्यों को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन सदस्यों को ई–मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं है, वे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए अपनी लॉग–इन प्रमाणिकताएं उत्पन्न कर सकते है।

ई–मेल पतों को पंजीकरण / अद्यतन करने का तरीका

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पतों को कम्पनी या उनके डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित लिंक : https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html के माध्यम से तथा उसमें दिए गए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करके, एजीएम के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) को प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु उसे अस्थायी रूप से पंजीकृत करें:

ई–मेल पतों के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्य कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:–

भौतिक रूप से रखे शेयरों के लिए	1. निम्नलिखित लिंक पर जाएं https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html 2. कम्पनी के नाम यानी एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को चुनें। 3. फोलियों नं., शेयरधारक का नाम, सर्टिफिकेट नं. पैन, मोबाइल नम्बर, ई–मेल–आईडी का उल्लेख करें तथा साथ में अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट आदि की स्व–साक्ष्यांकित प्रति दें।
डिमैटिरियलाइज्ड रूप में रखे शेयरों के लिए	इलेक्ट्रॉनिक विधि में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ई–मेल पतों, पैन व बैंक खाता विवरणों को उस डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत/नवीकृत करवाएं जहाँ उनके संबंधित डिमैट खाते है।

यदि ई–मेल पते की पंजीकरण प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न है, तो सदस्य कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट से rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर सम्पर्क कर सकते है।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
दिनांक : जूलाई 20, 2022
स्थान : नोएडा (यू.पी.)
मनीष आनंद
कम्पनी सचिव